2 जंतर मंतर पर पुलिस कार्यवाही का विरोध

5 संगठन, संवाद और राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर

6 बलूचिस्तान में स्वघोषित आजादी

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 11 प्रति सोमवार, 27 जुलाई 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मोहन सरकार का बढ़ता कर्ज, घटता जनविश्वास

हर महीने हजारों करोड़ का कर्ज, फिर भी जनता क्यों बेहाल?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का नया कर्ज लेने के निर्णय को लेकर चर्चा के केंद्र में है। पिछले कुछ समय से राज्य सरकार लगातार अंतराल पर हजारों करोड़ रुपये का ऋण ले रही है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लिया जा रहा यह कर्ज प्रदेश के भविष्य के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगा? क्या यह राशि ऐसे विकास कार्यों में निवेश हो रही है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे, या फिर इसका बड़ा हिस्सा केवल नियमित सरकारी खर्चों और पुरानी वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में व्यय हो रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों द्वारा कर्ज लेना कोई असामान्य बात नहीं है। प्रत्येक राज्य अपनी विकास योजनाओं, अधोसंरचना निर्माण और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए ऋण लेता है। लेकिन जब ऋण लेने की आवृत्ति लगातार बढ़ने लगे और लगभग प्रत्येक महीने हजारों करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने की नौबत आए, तब वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जनता यह जानना चाहती है कि आखिर बार-बार कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इस धनराशि का उपयोग किन प्राथमिकताओं के लिए किया जा रहा है।

सरकार की आर्थिक रणनीति पर प्रश्न

मध्यप्रदेश जैसे विशाल राज्य के सामने विकास की अनेक चुनौतियाँ हैं। एक ओर प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, दूसरी ओर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और संसाधनों की कमी की शिकायतें लगातार सामने आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद, आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हो पाया है। महँगाई भी आम नागरिक की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। रसोई से लेकर दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं तक की कीमतों ने मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित किया है। ऐसे समय में जनता की अपेक्षा रहती है कि सरकार अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान दे। यदि लगातार कर्ज लेने के बावजूद इन क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता, तो सरकार की आर्थिक रणनीति पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। (शेष पेज 3 पर)

युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की पहलें बनीं सशक्तिकरण का आधार

-विजया पाठक

किसी भी राज्य का भविष्य उसके युवाओं की ऊर्जा, कौशल और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित न रहकर उन्हें आत्मनिर्भर, कुशल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में अनेक योजनाओं को प्राथमिकता दी है। सरकार का प्रयास है कि युवा शिक्षा, कौशल, उद्यमिता और रोजगार के माध्यम से राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनें।साय सरकार ने युवाओं को केंद्र में रखकर कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वरोजगार, डिजिटल सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसी अनेक योजनाओं को गति दी है। सरकार का मानना है कि यदि युवा सशक्त होंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य तेजी से पूरा होगा।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार

राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न निवेश प्रस्तावों के माध्यम से आने वाले वर्षों में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। सरकार ने कौशल विकास को रोजगार का सबसे मजबूत माध्यम माना है। इसी उद्देश्य से राज्य में कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, कृषि आधारित उद्योग और सेवा क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। (शेष पेज 3 पर)

महादेव सट्टा एप्प घोटाले में बड़े खुलासे; कभी भी हो सकती है बघेल की गिरफ्तारी

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव एप्प सट्टा घोटाले में दिन-ब-दिन बड़े खुलासे होने से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने पूछताछ के दौरान कुछ खुलासों से पूर्व मुख्यमंत्री बघेल पर कभी भी कानून के हाथ पहुँच सकते हैं। रामगोपाल के बाद दिल्ली में विकास गर्ग के एजेंसियों के हत्थे चढ़ने से पूर्व मुख्यमंत्री की सांसें फूली हुई हैं। अग्रवाल की रिमांड अवधि 17 जुलाई के ख़त्म होते ही पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भी एजेंसियों के हत्थे चढ़ने की कगार पर हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल, उनके सलाहकार रहे विनोद वर्मा, 2001, 2005 और 2007 बैच के आईपीएस क्रमशः आनंद छाबड़ा, शेख़ आरिफ और प्रशांत अग्रवाल समेत अन्य सट्टा कारोबारियों से विकास गर्ग के करीबी संबंध बताएं जाते हैं। (शेष पेज 3 पर)

जंतर मंतर पर पुलिस कार्यवाही का विरोध, छात्रों ने दिया धरना

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। विगत 32 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के छात्रों द्वारा नीट एग्जाम में पेपर लीक मामले में शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर चल रहे आंदोलन को टिमरनी में भी छात्र छात्राओं ने समर्थन करते हुए स्थानीय स्टेशन चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया तथा दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज और सरकार की मनमानी का जोरदार विरोध किया एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार टिमरनी को सौंपा। छात्रों ने इस आंदोलन को पुस्तक सत्याग्रह नाम दिया। लगभग 2 घंटे तक चले धरना आंदोलन में छात्रों को कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन दिया तथा धरना आंदोलन में सहभागिता कर छात्रों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद पटेल, कांग्रेस नेता गंगाराम गुर्जर, राजेंद्र नागरे, दिनेश चमन, जितेंद्र सोनकिया, शहजाद खान, रमेश तिवारी ने भी अपने विचार रखे तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा और छात्रों पर लाठी चार्ज की निंदा की धरने मे बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजेश नाथ, शशि वर्मा, मनवीर रघुवंशी, दिनेश विश्कर्मा, यूसुफ गौरी, इजराइल खान, ओम मिश्रा, आदित्य पटेल, भगतराम जाट, शेंकी उपाध्याय, शिवम कनोजिया, प्रताप सिंह राजपूत, संतु राजपूत सहित अनेक लोग शामिल थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्य साईं ग्राम के सेवा मॉडल को बताया प्रेरक उदाहरण

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का आधार केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित समाज है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को सुशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजसेवी संस्थाओं के अनुभव, नवाचार और सेवा भावना से जनकल्याण के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल, रायपुर द्वारा पूर्णतः निःशुल्क बाल हृदय शल्य चिकित्सा के माध्यम से हजारों बच्चों को नया जीवन देने के कार्य की मुख्यमंत्री ने विशेष सराहना की। उन्होंने इसे मानवता और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए अस्पताल के विस्तार, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की स्थापना तथा भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय मूल्य आधारित शिक्षा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में विश्व के लगभग 25 देशों से आए 100 से अधिक शिक्षकों एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आधुनिक शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सेवा, करुणा, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी आधार होनी चाहिए। मूल्य आधारित शिक्षा ही संवेदनशील नागरिकों और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। मुख्यमंत्री साय ने कर्नाटक के सत्य साई ग्राम, मुद्देनहल्ली का दौरा कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित समग्र सेवा मॉडल का अवलोकन किया। उन्होंने वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के संस्थापक सद्गुरु मधुसूदन साई से भेंट कर छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी सेवाओं के विस्तार, विशेष रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट द्वारा संचालित साईश्योर न्यूट्रास्यूटिकल्स इकाई का भी अवलोकन किया। साईश्योर मल्टी-न्यूट्रिएंट हेल्थ मिक्स के माध्यम से देश के 25 राज्यों एवं 4 केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग एक करोड़ बच्चों तक पोषण सहायता पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे नवाचारों के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर को और बेहतर बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के लगभग 300 युवाओं को यहां नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ सेवा भाव से प्रेरित दक्ष स्वास्थ्य मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, नियम तोड़ने वाले दो वाहनों पर 11 हजार का चालान

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। कलेक्टर रजनी सिंह के मार्गदर्शन में जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने करेली नगर के विभिन्न स्कूलों में संचालित वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान पीडीएस स्कूल, कार्मेल स्कूल, माउंट लिटेरा स्कूल, सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल और ज्ञान सागर स्कूल का निरीक्षण कर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के पालन की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान सभी स्कूल प्रबंधन को विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा स्कूल वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। जांच में कुल 11,000 की चालानी कार्रवाई की गई।

जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने स्पष्ट कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल वाहनों की जांच अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डोंगरवाड़ा सरपंच माखन कीर को सरपंची प्रभार दिए जाने पर दर्ज कराई आपत्ति, मामला गरमाया

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। नर्मदा नदी किनारे स्थित ग्राम पंचायत डोंगरवाड़ा का सरपंच पद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कमिश्नर द्वारा माखन कीर का जिलाबदर निरस्त किए जाने के उपरांत प्रशासन द्वारा पुनः सरपंच का प्रभार सौंप दिया गया है। जिसको लेकर सरपंच कैलाश दायमा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए पुनः सरपंच पद पर प्रभार दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। कैलाश दायमा ने पत्रकार वार्ता में उक्त विषय पर अपनी बात रखी है। जिलाबदर निरस्त होने के उपरांत माखन कीर को जनपद सीईओ के आदेश पर सरपंच प्रभार दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि वह उक्त आदेश के विरुद्ध अब माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। मामले में जिला प्रशासन द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। वही मामले में जनपद सीईओ रंजीत ताराम ने बताया कि कमिश्नर द्वारा माखन कीर का जिलाबदर निरस्त किए जाने के उपरांत पुनः सरपंच का प्रभार नियमानुसार दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम के आदेश पर उक्त प्रभार सौंपा गया है। अवगत हो कि ग्राम पंचायत डोंगरवाड़ा के सरपंच माखन कीर को पूर्व कलेक्टर सोनिया मीणा द्वारा 16 मार्च को जिलाबदर कर दिया गया था। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 04 मई को स्थानापन्न सरपंच के पद पर विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से पंचों द्वारा कैलाश दायमा को स्थानापन्न सरपंच नियुक्त किया गया। इसके बाद में निवर्तमान सरपंच माखन कीर द्वारा कलेक्टर के जिलाबदर आदेश के विरुद्ध नर्मदापुरम कमिश्नर के अपील प्रस्तुत की गई। अपील में प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत आयुक्त नर्मदापुरम ने 02 मई को कलेक्टर के आदेश का परीक्षण करते हुए संशोधित कर निरस्त कर दिया।

महादेव सट्टा एप्प घोटाले में बड़े खुलासे; कभी भी हो सकती है बघेल की गिरफ्तारी

(पेज 1 का शेष)

ईओडब्ल्यू की टीम विभिन्न घोटालों और नगद रकम की अफ़रा-तफ़री को लेकर राम गोपाल अग्रवाल से निर्णायक पूछताछ में जुटी है। यह भी बताया जा रहा है, कि EbixCash के चेयरमैन विकास गर्ग और पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बीच सौरभ चंद्राकर के माध्यम से बड़ी रकम का लेन-देन तय किया जाता था। यही नहीं, महादेव सट्टा कारोबार का रायपुर में देश का मुख्य ठिकाना बनाने के लिए लगभग आधा दर्जन आईपीएस अधिकारियों को भी बिजनेस पार्टनर बनाया गया था। सट्टा कारोबार को संरक्षण देने के लिए बतौर "प्रोटेक्शन मनी" पुलिस के कई आला अधिकारियों को नगद रकम देने की बांगडोर एएसआई चंद्र भूषण वर्मा को सौंपी गई थी। यह भी बताया जा रहा है, कि इन आईपीएस अधिकारियों के अलावा एएसपी और सीएसपी से लेकर कई स्थानीय थानेदारों का एक बड़ा दस्ता महादेव एप्प सट्टा कारोबार से "प्रोटेक्शन मनी" वसूल रहा था। ईडी की फाइलों में एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का नाम उन मुख्य गवाहों की सूची में दर्ज बताया जाता है, जिन्होंने, सट्टा संचालन और "प्रोटेक्शन मनी" से जुड़ी रकम पुलिस महकमें के जिम्मेदार अधिकारियों के ठिकानों तक पहुंचाई थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दागी अफसरों की भूमिका का भी हवाला दिया है। इसमें ख़ुफ़िया के अन्य निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के नाम भी दर्ज बताए जाते हैं।

महादेव सट्टा ऐप मामले से कांग्रेस की छबि धूमिल

छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप के कारण प्रदेश में कांग्रेस की छबि धूमिल होती जा रही है। खासकर भूपेश बघेल के किये गये कारनामों से पार्टी दागदार साबित हो रही है। बावजूद उसके कांग्रेस आलाकमान अभी भी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार नहीं कर पा रहा है। जबकि राज्य भी चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव जैसे कर्मठ और जुझारू नेता हैं जो आज भी पार्टी की खोई हुई साख का वापिस ला सकते हैं लेकिन पार्टी इस पर विचार ही नहीं कर रही है। महादेव सट्टा ऐप का दंश आज तक कांग्रेस भुगत रही है और जब तक भूपेश बघेल इसमें जुड़े रहेंगे यह दाग बरकरार रहेंगे। इससे छुटकारा पाने और पार्टी की साख बचाने का एक ही तरीका है कि वह बघेल से दूरी बना ले, जिसका संदेश भी सकारात्मक जायेगा।

आधा दर्जन आरोपी खा चुके जेल की हवा, फिलहाल जमानत पर

गौरतलब है कि महादेव ऐप सट्टा मामले में अब तक आधा सैंकड़ा से ज्यादा आरोपी जेल की हवा खा चुके हैं। इसमें से लगभग सभी जमानत पर रिहा हैं। इस मामले में जहाँ मुख्य आरोपियों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की गिरफ़्तारी का मामला अब तक अधर में लटका नजर आ रहा है। वही, अदालत में दाखिल सीबीआई की नई चार्जशीट जितने गुनाहों के तथ्यों को उजागर कर रही है, उससे कहीं ज्यादा सवाल विवेचना को लेकर सुर्ख़ियों में है। मार्च 2025 में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ समेत 60 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। जांच में अवैध सट्टा नेटवर्क को संचालित करने के कुछ एक पुलिस अधिकारियों को हर महीने बाकायदा "प्रोटेक्शन मनी" मुहैया कराने का जो दस्तावेज सामने आया था, उसमें आईपीएस आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, पूर्व एएसपी संजय ध्रुव और पुलिस अधिकारी अभिषेक माहेश्वरी सहित कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी तलाशी और छापेमारी का घटनाक्रम सामने आया था।

युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की पहलें बनीं सशक्तिकरण का आधार

(पेज 1 का शेष)

युवाओं में नई उम्मीद जगी है

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी सरकार ने सकारात्मक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति देने, चयन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने तथा समयबद्ध नियुक्तियों पर जोर दिया जा रहा है। इससे लंबे समय से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं में नई उम्मीद जगी है। स्वरोजगार को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। युवा उद्यमियों को बैंक ऋण, प्रशिक्षण, विपणन सहायता और विभिन्न विभागों की योजनाओं से जोड़कर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवाचार आधारित उद्यमों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि प्रदेश के युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बन सकें। ग्रामीण युवाओं के लिए सरकार ने विशेष योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, वन उत्पाद प्रसंस्करण और लघु उद्योगों के माध्यम से गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पलायन रोकने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। डिजिटल तकनीक के बढ़ते महत्व को देखते हुए राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर भी लगातार काम कर रही है। युवाओं को ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे नई पीढ़ी आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर रही है।

अनुसंधान और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भी गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, तकनीकी शिक्षा के विस्तार और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देकर युवाओं

को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही खेल, नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आदिवासी और दूरस्थ अंचलों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना भी साय सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, छात्रावास सुविधाओं और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। सरकार का यह भी प्रयास है कि युवाओं को केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इससे रोजगार के विविध अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

क्षमता के अनुरूप अवसर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार यह कहते रहे हैं कि राज्य का सबसे बड़ा संसाधन उसकी युवा शक्ति है। इसी सोच के अनुरूप उनकी सरकार रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता, डिजिटल सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां प्रत्येक युवा अपनी क्षमता के अनुरूप अवसर प्राप्त कर सके।विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि कौशल विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन की वर्तमान गति बनी रहती है तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ युवा शक्ति के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और मजबूत कर सकता है। युवाओं के सपनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में साय सरकार की यह पहल केवल योजनाओं तक सीमित नहीं दिखाई देती, बल्कि एक ऐसे भविष्य की आधारशिला रखने का प्रयास है, जहां शिक्षा, कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता मिलकर नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है युवा सशक्त होंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा और यही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव बनेगी।

उधार की अर्थव्यवस्था पर टिकी मध्यप्रदेश सरकार?

(पेज 1 का शेष)

रोजगार के पर्याप्त अवसरों की प्रतीक्षा

सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि प्रदेश का युवा आज भी रोजगार के पर्याप्त अवसरों की प्रतीक्षा कर रहा है। औद्योगिक निवेश की घोषणाएँ अवश्य होती हैं, लेकिन उनके धरातल पर उतरने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने में अभी भी समय लग रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितता, रिक्त पदों पर धीमी भर्ती प्रक्रिया और निजी क्षेत्र में सीमित अवसरों के कारण युवाओं में असंतोष की भावना समय-समय पर दिखाई देती रही है। यदि सरकार लगातार ऋण ले रही है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा रोजगार सृजन और कौशल विकास पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इतिहास पर दृष्टि डालें तो मध्यप्रदेश की विभिन्न सरकारों ने भी आवश्यकता के अनुसार ऋण लिया है, लेकिन वर्तमान समय में जिस गति से बार-बार कर्ज लिया जा रहा है, उसने राजनीतिक बहस को नया आयाम दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऋण आधारित वित्तीय प्रबंधन की ओर बढ़ रही है, जबकि सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि अधोसंरचना विकास, सिंचाई, सड़क, निवेश और अन्य दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश आवश्यक है।

ब्याज भुगतान का बोझ भी बढ़ाता

वित्तीय विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि ऋण का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण, औद्योगिक विस्तार, सिंचाई परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में किया जाए, तो वह भविष्य में आर्थिक विकास का आधार बन सकता है। लेकिन यदि ऋण का बड़ा हिस्सा केवल राजस्व व्यय, वेतन, ब्याज भुगतान अथवा अन्य नियमित खर्चों में ही समाप्त हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियों पर ऋण का बोझ बढ़ना तय है। राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल विकास परियोजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी है। आर्थिक विकास तभी स्थायी माना जाएगा जब उसके साथ राजकोषीय संतुलन भी कायम रहे। बढ़ता हुआ ऋण भविष्य में ब्याज भुगतान का बोझ भी बढ़ाता है, जिसका प्रभाव अंततः विकास योजनाओं पर पड़ सकता है।

सरकार के लिए चुनौती

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार प्रदेश की जनता के सामने एक स्पष्ट आर्थिक रोडमैप प्रस्तुत करे। यह बताया जाए कि हाल के वर्षों में लिए गए हजारों करोड़ रुपये के ऋण से कौन-कौन सी परियोजनाएँ पूरी हुईं, कितने नए रोजगार सृजित हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या ठोस परिवर्तन आया तथा प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए कौन-सी दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जा रही है। केवल ऋण लेकर विकास का दावा करना पर्याप्त नहीं है; जनता परिणाम भी देखना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने अभी कार्यकाल का पर्याप्त समय है। ऐसे में उनके लिए यह अवसर भी है कि वे वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाकर जनता का विश्वास मजबूत करें। यदि ऋण का उपयोग वास्तव में उत्पादक निवेश, अधोसंरचना निर्माण और रोजगार सृजन में होता है, तो उसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। लेकिन यदि जनता को केवल बढ़ता हुआ कर्ज और मूलभूत सुविधाओं में अपेक्षित सुधार का अभाव ही दिखाई देता रहा, तो यह राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से सरकार के लिए चुनौती बन सकता है।

सम्पादकीय

जंतर-मंतर का संदेश, युवाओं की आवाज़ को सुनने का समय

दिल्ली का जंतर-मंतर केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। जब भी देश के किसी वर्ग को लगता है कि उसकी बात पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जा रही, तब जंतर-मंतर उसकी आवाज बनने का माध्यम बनता है। इन दिनों युवाओं का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर इस प्रश्न को सामने ला रहा है कि देश की सबसे बड़ी युवा आबादी की अपेक्षाओं और सरकार की नीतियों के बीच कितना संतुलन स्थापित हो पा रहा है। भारत विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है। यह युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। यही युवा आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, उद्योग और प्रशासन की दिशा तय करेंगे। ऐसे में यदि यही वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाए, तो इसे केवल कानून-व्यवस्था का विषय मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे मौजूद कारणों को समझना और उनका समाधान तलाशना अधिक आवश्यक है। देशभर में युवाओं की प्रमुख चिंताओं में रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब, परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाएं, परिणाम घोषित होने में देरी और रिक्त पदों पर समय पर नियुक्तियां न होना शामिल हैं। वर्षों तक तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए हर भर्ती प्रक्रिया केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनके भविष्य की उम्मीद होती है। जब यह प्रक्रिया किसी कारण से प्रभावित होती है, तो उसका सीधा असर उनके आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं पर पड़ता है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखने का अधिकार प्राप्त है। यदि युवा शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, तो उनके साथ संवाद स्थापित करना सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों की भी यह जिम्मेदारी है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और किसी भी प्रकार से सार्वजनिक व्यवस्था या आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित न करे। युवाओं की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं से संभव नहीं है। इसके लिए समयबद्ध भर्ती कैलेंडर, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, आधुनिक तकनीक के माध्यम से परीक्षा सुरक्षा, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति और शिकायतों के त्वरित निवारण जैसी ठोस व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की गति अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मानी जा रही है। सरकारों के सामने चुनौती केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास को भी बनाए रखना है। जब किसी परीक्षा में अनियमितता या विलंब की खबर सामने आती है, तो उसका प्रभाव लाखों अभ्यर्थियों के मनोबल पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संबंधित संस्थाएं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध तरीके से कार्य करें।

देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। इसलिए युवाओं का विश्वास बनाए रखना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। संवाद, पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय और संवेदनशील प्रशासन ही ऐसे उपाय हैं, जिनसे जंतर-मंतर जैसे आंदोलनों की आवश्यकता धीरे-धीरे कम हो सकती है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब युवाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के लिए सड़कों पर उतरने के बजाय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास हो।

सियासी गहमागहमी

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से झुक गई मोदी सरकार

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उसका राजनीतिक महत्व केवल एक मंत्री के पद छोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा। यह सत्ता और जनभावनाओं के बीच संबंधों की भी परीक्षा होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब किसी बड़े मुद्दे पर जनदबाव बढ़ता है, तब सरकारें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेती हैं और ऐसे निर्णयों के राजनीतिक संदेश भी व्यापक होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से भाजपा के प्रमुख नेताओं में रहे हैं और संगठन तथा सरकार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। ऐसे में उनसे जुड़ा कोई भी घटनाक्रम स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बनेगा। लोकतंत्र में किसी भी विवाद का सबसे प्रभावी समाधान पारदर्शिता, तथ्य और जवाबदेही के आधार पर ही संभव है। अंततः किसी भी सरकार की विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वह जनभावनाओं, संस्थागत मूल्यों और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है। यही लोकतांत्रिक परिपक्वता का वास्तविक पैमाना भी है।

कमलनाथ की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश की राजनीति में अक्सर यह देखने को मिलता है कि सरकारें बदलने के साथ कई योजनाओं की दिशा भी बदल जाती है। हालांकि कुछ ऐसी पहलें भी होती हैं, जिन्हें जनहित में नई सरकारें भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। हाल के समय में गौशाला जैसी कुछ योजनाओं को लेकर यह चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में शुरू की गई पहल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार नए स्वरूप में आगे बढ़ा रही है। राजनीतिक मतभेदों से इतर यदि कोई योजना जनहित में उपयोगी साबित होती है, तो उसका निरंतर क्रियान्वयन लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत माना जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि विकास की प्रक्रिया किसी एक सरकार तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह निरंतर चलने वाली यात्रा है। अंततः जनता की अपेक्षा यही रहती है कि सरकारें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर उन योजनाओं को प्राथमिकता दें, जिनका सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे education system को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।

शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है।

सड़कों पर आ कर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत-बहुत बधाई।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर में नल पहुंचना था। लेकिन अब CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 27000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 34 लाख घरों में नल कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संगठन, संवाद और शिक्षा सुधार की राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने संगठनात्मक क्षमता, प्रशासनिक अनुभव और जनसंपर्क की कुशलता के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऐसे ही नेताओं में प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने संगठन और सरकार, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। ऊर्जा क्षेत्र से लेकर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उनके कार्यकाल ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में स्थापित किया है।

धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर (जिला अंगुल) में हुआ। उनके पिता डॉ. देवेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। राजनीतिक वातावरण में पले-बढ़े धर्मेंद्र प्रधान ने प्रारंभ से ही सार्वजनिक जीवन में रुचि दिखाई। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और छात्र जीवन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़कर सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई।

छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक का उनका सफर निरंतर सक्रियता, संगठनात्मक प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता का उदाहरण माना जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने युवाओं के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई। बाद में उन्हें भाजपा संगठन में कई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए, जिन्हें उन्होंने प्रभावी ढंग से निभाया। धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा के माध्यम से संसद पहुंचे और समय के साथ केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया। इसके बाद उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल कीं। देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की दिशा में उनके प्रयासों की व्यापक चर्चा हुई।

उनके कार्यकाल की सबसे चर्चित उपलब्धियों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभावी क्रियान्वयन रहा। इस योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में इस योजना को केंद्र सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी पहलों में गिना जाता है। वर्ष 2021 में धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस दायित्व के साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, भारतीय भाषाओं के संवर्धन और शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को अधिक लचीला, रोजगारोन्मुख और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने के प्रयास उनके कार्यकाल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। साथ ही डिजिटल माध्यमों से शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, कौशल आधारित प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने तथा विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने की दिशा में अनेक पहल की गईं।

धर्मेंद्र प्रधान अपनी सरल कार्यशैली, संवाद क्षमता और संगठन के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। वे अक्सर कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहते हैं और जमीनी स्तर पर संवाद स्थापित करने को अपनी राजनीतिक शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। भाजपा संगठन में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक विस्तार, दोनों क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं।

राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नीति निर्माण, संगठन विस्तार और जनहित से जुड़े विषयों पर सक्रिय भागीदारी निभाने वाले नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। संसद में उनके वक्तव्य, विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण और प्रशासनिक अनुभव उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल करते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठनात्मक कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री तक का सफर निरंतर परिश्रम, अनुशासन और सक्रिय जनसंपर्क के बल पर तय किया है। ऊर्जा, शिक्षा और संगठन के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली, सक्रिय और दूरदर्शी जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है।

खनन माफिया और सरकार

रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और समाजवादी नेता

पिछले दिनों मुरैना में पत्थर खदानों से रेत खनन के समाचार प्रमुखता से समाचार पत्रों में आये। खनन माफिया का हौसला इतना बढ़ा है कि उन्होंने अनेक अधिकारियों के वाहन रोकने का प्रयास किया, उनके ऊपर ट्रेक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। कई कर्मचारी वन और राजस्व विभाग के घायल हुए और कुछ तो शहीद हो गये। कई अखबारों ने खनन वालों के बयान छापे कि वे पुलिस थाने के सामने से निकलते हैं, परंतु उन्हें रोकने की हिम्मत पुलिस में नहीं है। क्योंकि खनन करने वाले बंदूक रखते हैं और कर्मचारी भी जानते हैं कि वह गोली भी मार सकते हैं। मुरैना के राज्य सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया है कि खनन करने वाले नौजवानों की लाचारी है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। इस पक्ष से इंकार नहीं किया जा सकता कि बेरोजगारी भी एक कारण है परंतु यह भी तथ्य है कि अब बेरोजगार नौजवान तो खनन करने वाले हैं या ट्रेक्टर आदि चलाने वाले हैं, याने एक प्रकार के अल्प वेतन भोगी श्रमिक जैसे हैं। इनके मालिक बड़े माफिया हैं जो इन नौजवानों से यह कार्य कराते और वे बेरोजगार नहीं हैं। बल्कि वह करोड़पति हैं जिनके पास बड़े-बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं और अपराध करने वाले उनके कर्मचारी हैं। वैसे तो यह खनन का सिलसिला कोई आज का नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत तो 1971 के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके बेटे स्वरू संजय गांधी सत्ता के अघोषित नियंत्रक थे, तभी हो चुकी थी। दिल्ली के आसपास के 30-40 किमी के दायरे के पहाड़ों को खोदने वाले उस समय सभी कांग्रेस समर्थक थे। स्वरू संजय गांधी के लठैत थे और आज वे भी दिल्ली के पाश इलाकों में बड़े-बड़े मकान बनाकर रह रहे हैं और कारों में चल रहे हैं।

सत्ता के संरक्षण में वह छोटी हो या बड़ी हो खनन माफिया पनपते हैं। और इसी प्रकार रेत का खनन भी देश के अधिकांश इलाकों में बड़ी मझौली या छोटी नदियों के पास रेत का खनन कराने वाले रेत माफिया और आमतौर पर माफिया सरगना उस स्थानीय जाति, जिसकी संख्या व बाहुबल होता है, के होते हैं। खनन करने वाले उनके कर्मचारी होते हैं। खनन से देश के पर्यावरण पर जो असर पड़ा है इसका कोई विधिवत आंकलन अभी तक नहीं हुआ है। न सरकारों ने कराया है और न किसी अन्य प्रकृति के संरक्षकों ने कराया है। सरकारों से तो उम्मीद करना ही व्यर्थ है क्योंकि आमतौर पर यह सभी खनन माफिया सरकारों के संरक्षण में ही पलते हैं। सत्ता के मुखिया की जाति के नाम उनके ट्रेक्टरों और वाहनों पर लिखे रहते हैं, उनसे दुर्घटनायें होती हैं, निर्दोष लोग मरते हैं, परंतु सरकार के मुखिया के संरक्षण के चलते प्रशासन व पुलिस उन्हें रोकना, पकड़ना या अपराध दर्ज करना तो दूर उन्हें दूर से सलाम करते हैं। पत्थर और रेत के खनन से कितने ही इलाकों में खदानें बन गई हैं और इन खदानों में पानी भरने से अनजाने में लोग डूबकर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें इनका कोई अनुमान नहीं होता। इन सामान्य व निर्दोष लोगों को सरकारें भी कोई मुआवजा नहीं देती क्योंकि वे दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में रहने वाले होते हैं। लगातार नदियों से रेत निकालने से जो नदियों के जल का शुद्धिकरण होता था वह घट रहा है और नदियां मिटटी के दलदल में बदल रही हैं। पत्थरों को खोदने के लिये वनों को काटा जाता है और वनों की संख्या इस कारण से घट रही है परंतु आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात में पर्यावरण नष्ट करने वाले, प्रकृति को नष्ट करने वाले इन खनन माफियाओं के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की? हो सकता है कि उसका एक कारण यह भी हो कि इन दिनों देश के लगभग 22 राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकारें हैं जो उनकी अपनी है और अपनी सरकारों के अपराधों के बारे में बोलना उनकी संस्कृति नहीं है बल्कि अपनों के अपराध पर पर्दा डालना और दूसरों के अपराध को बढ़ा-चढ़ाकर बताना उनकी शैली है या राजनैतिक चतुराई है। अगर यह खनन नहीं रुका तो कुछ वर्षों के बाद देश की बड़ी व पवित्र मानी जाने वाली नदियां भी मिटटी के दलदल में बदल जायेगी, वही बड़े-बड़े पहाड़ भी पत्थरों के टीले बन जायेंगे। आज सरकार के वन मंत्री की छत्रछाया में भारत सरकार ने तो अरावली पर्वत में खनन की अनुमति को लेकर जो योजना प्रस्तुत की थी, उसमें तो यह कह दिया गया था कि अगर 200 मी. के ऊपर पहाड़ है, तो वही पहाड़ माना जायेगा तथा उसमें खनन की अनुमति दी जा सकेगी। भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बगैर अध्ययन व विचार कर स्वीकृति की मुहर लगा दी, पर सारे राजस्थान व देश से जब अरावली बचाओ का अभियान शुरू हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दोषी बताते हुए अपना आदेश वापिस लिया। यह सर्वविदित है कि अरावली पर्वत में बड़ी संख्या में बड़ी पर्वत श्रृंखलायें हैं और यह सभी पर्वतों में होती है। अगर एक बार यह पर्वत श्रृंखलायें कटकर साफ हो जाती, चटटान व पर्वतों को खोद दिया जाता तो राजस्थान का क्या होता? प्राण वायु कहां से मिलती? वर्षा के लिये बादल कहां से रुकते, कितना सूखा पड़ता इन सबके बारे में सरकारों को कोई चिंता नहीं। आज धारणा यह बन चुकी है कि सरकारों व प्रशासन तंत्र को केवल रिश्वत चिहये चाहे देश का कुछ भी हो। यह पर्वत श्रृंखला मात्र पर्यावरण की संरक्षक नहीं हैं बल्कि यह देश के गौरवशाली इतिहास की कहानियाँ भी हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में देश के पुरखों ने शौर्य का प्रदर्शन किया था और देशभर में हजारों आंचलिक गौरव गाथायें हैं, जो इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं में संरक्षित है। निसंदेह राजस्थान के लोगों ने अरावली बचाने की शुरुआत की वह देश के लिये प्रेरक संदेश है और शायद ऐसी जनमानस और आमजन की पहल अब देश के पर्यावरण वनों, नदियों, इतिहास और संस्कृति को बचा सकती है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में अरावली पर्वत को लेकर कुछ सख्त रुख अपनाया है उसका मप्र के बाहर राजस्थान, उप्र, हरियाणा, बिहार आदि में क्या असर हुआ है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है परंतु मप्र में प्रदेश के मुख्य सचिव ने अवश्य कुछ सख्त पहल की है तथा इन खनन क्षेत्रों व माफियाओं को रोकने के लिये विशेष पुलिस बल भेजे हैं तथा कहा कि खनन रुकना चाहिये, बजट का रोना न रोयें। इससे लगता है कि सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट के दबाव में और कुछ भाजपा के अंतर दलीय राजनैतिक सभी कारणों के कारण कुछ सक्रिय हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रदेश में विशेष तौर से मुरैना में तो खनन रुकेगा। हालांकि होना तो यह चाहिए कि जितने खनन माफिया प्रदेश में हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उनके पास अरबों की संपत्ति कहां से आई वह जप्त होनी चाहिये और उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कदम उठायेगी। दूसरी तरफ मुझे यह भी आशंका है कि जो हजारों नौजवान और ग्रामीणजन इस खनन के अवैध धंधे में लगे थे, खोदने से लेकर लाने ले जाने तक उनके सुरक्षा पहरी बनकर आदि-आदि, वे सब अपना पेट भरने के लिये अपराध की ओर मुड़ सकते हैं। इसलिये सरकार को चाहिए कि इन अंचलों के नौजवानों के लिये रोजगार के लिये, साथ-साथ विशेष अभियान चलाये ताकि उन्हें वैकल्पिक रोजगार मिल सके और वे अपराध की दुनिया में प्रवेश न करें।

मुख्यमंत्री धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जन समस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित एवं सुशासन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी, जब आम नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा शिकायतकर्ता को समाधान की प्रगति से भी अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार का दायित्व है। प्रत्येक अधिकारी जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए जनता की समस्याओं के समाधान में पूर्ण संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व का परिचय दें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए, जिससे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय एवं राहत मिल सके।

बलूचिस्तान में स्वघोषित आजादी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से सोशल मीडिया पर एक स्वघोषित बयान और पत्र वायरल हुए हैं, जिसमें बलूच नेता मीर यार बलूच और कुछ पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। अपना नया झंडा और राष्ट्रगान जारी करते हुए सरकार बना लेने का दावा भी किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने 27 पुलिसकर्मियों का आपहरण कर हत्या कर दी है। इससे बलूच आंदोलन उत्साहित हुआ है और वे जल्द कानूनी रूप में आजादी मिल जाने की उम्मीद करने लगे हैं। हालांकि इस हत्याकांड के बाद पाक सेना ने बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर, पुलिस व आतंकवाद निरोधक बल के साथ ऑपरेशन शाबान शुरू कर दिया है। पाक के सामने अब बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बीएलए को इजरायली खुफिया एजेंसियों से धन, तकनीक और आधुनिक संचार उपकरण मिल रहे हैं। पाक सेना ने लड़कों के पास से स्टारलिंग उपकरण जब्त किए हैं। पाक सेना का यह भी आरोप है कि अफगानिस्तान बीएलए को विद्रोही बलूचों ने करीब 85 प्रतिशत बलूचिस्तान की भूमि पर काबिज होने का दावा किया है। बलूच कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील भी कर दी है। यह पाकिस्तान का वह प्रमुख क्षेत्र है, जहां से चीन-पाक आर्थिक गलियारा गुजर रहा है। इसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यही वह क्षेत्र है, जहां अत्यंत दुर्लभ खनिज एवं प्राकृतिक गैसें उपलब्ध हैं। यही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही है, वह अब सफलता के शिखर पर है। बलूचिस्तान को नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो 1971 के बाद पाकिस्तान की भूमि पर दूसरा बड़ा विभाजन दिखाई देगा। 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को सैनिक मदद देकर पाक के दो टुकड़े कर दिए थे। अब बलूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग कर रहे हैं।

प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच को बलूच के लोगों के अधिकारों की वकालात के लिए जाने जाते हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाक सेना को बलूच सीमा क्षेत्र से बाहर कर देने का आग्रह भी किया है। यदि बलूच स्वतंत्र देश बन जाता है तो भारत-पाक युद्ध के बीच 1971 की तरह एक युगांतरकारी घटना देखने को मिलेगी, जिसमें बलूचों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव में भारत भी भागीदार हो सकता है। बलूचों की स्वतंत्रता की संभावना का अहसास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जताया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान पर अब सेना और सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। यहां के हालात इतने खराब हैं कि सरकारी मंत्री तक बाहरी सुरक्षा के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। सेना के जवान अपने ही देश में बंकरों में छिपे हैं।

बलूचिस्तान में विद्रोह की आग चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद कर किया था। कालांतर में सैनिक तानाशाह जिया उल हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलूच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाबमिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खेरबक्ष मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फिनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ा हुआ। जगह-जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई।

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। अतएव पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है। बीएलए जब साल 2000 में वजूद में आया था तब इसके लड़ाकों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी। जिसमें करीब 150 आत्मघाती दस्ते शामिल थे। सरदार अकबर खान बुगती एक समय बलूचिस्तान के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसीलिए वे बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तभी से यह संगठन पाक सेना से लोहा ले रहा है। वर्तमान में बलूच अलगाववादी और तालिबान के बीच निरंतर निकटता बढ़ रही है। वैसे भी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाक सरकार ने भी स्वीकार किया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ही बलूच लड़ाकों को प्रशिक्षित कर रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में अब महिलाओं ने भी बीएलए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलूच नागरिकों के दमन चक्र के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया है। इस सच्चाई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी स्वीकारा है।

पाक की आजादी के साथ बलूचिस्तान का मुद्दा जुड़ा है। पाक की कुल भूमि का 43.6 फीसदी हिस्सा केवल बलूचिस्तान का है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 01 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं, पाक की कुल आबादी में इनकी छह प्रतिशत की भागीदारी है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किमी है। यहां हिंदू, सिख और ईसाई भी रहते हैं। इनमें आपस में खूब भाईचारा है। भगवान शिव की पत्नी सती का हिंगलाज मंदिर इसी बलूच क्षेत्र में आता है। अनेक मुसलमान भी देवी सती की पूजा-अर्चना करते हैं। क्योंकि ये धर्मांतरित हैं। यहां से कभी सांप्रदायिक दंगों की खबरें नहीं आती हैं। 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। पीओके और बलूचिस्तान पाक के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह, जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब व लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण देता रहा है, वहीं बलूचिस्तान की भूमि से खनिज व तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए है। यहां सोना, तांबा, कोयला और प्राकृतिक गैसों के बड़े भंडार है, लेकिन इनसे कमाई का बड़ा हिस्सा पाक सरकार, सेना और चीनी कंपनियां हथिया लेती हैं। इस कारण लोगों का गुस्सा उबाल पर है।

बलूचिस्तान की कलात रियासत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शामिल हो गया था। लेकिन बलूचिस्तान ने पाक में विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। लिहाजा यहां अलगाव की आग निरंतर बनी रही है। नतीजतन 2001 में यहां 50 हजार लोगों की हत्या पाक सेना ने कर दी थी। इसके बाद 2006 में अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले 20 हजार सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया गया था, जिनका आज तक पता नहीं है। 2015 में 157 लोगों के अंग-भंग किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने जाने-माने एक्टिविस्ट बाबा जान को भी हिरासत में लिया हुआ है। पिछले 20 साल से जारी दमन की इस सूची का खुलासा एक अमेरिकी संस्था ने किया है। वाशिंगटन में कार्यरत संस्था गिलगित-बलूचिस्तान नेशनल कांग्रेस के सेंग सिरिंग ने मोदी द्वारा उठाए, इस सवाल का समर्थन किया है कि 'पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में लोगों पर होने वाले जुल्म एवं अत्याचार के बाबत पाक को दुनिया के समक्ष जवाब देना होगा? पाक तो जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में भागीदार बने?

युद्ध का पर्यावरण पर होता है खतरनाक असर

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

युद्धों की विभीषिका न केवल मानवीय त्रासदियों और आर्थिक तबाहियों के रूप में सामने आती है, बल्कि इनसे जो छिपा हुआ पर्यावरणीय विनाश दफ़्तर में बैठी समझौतों की सुस्ती के बीच अनदेखा रह जाता है, वह कहीं अधिक खतरनाक है। रात-दिन चल रहे हवाई हमलों ने हवा में मिट्टी के सूक्ष्म कण, धातु युक्त अवशेष और रासायनिक प्रदूषक अनगिनत घरों में प्रवेश करवा दिए हैं। यह प्रदूषण केवल सांस लेने में असुविधा भर नहीं बढ़ाता, बल्कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की अन्य पुरानी बीमारियों के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि भी ला रहा है। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयों के आँकड़े बताते हैं कि युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों में श्वसन संबंधी रोगी अक्सर दोगुने तक पहुँच जाते हैं। फिर भी यह क्षति वायु तक सीमित नहीं है। यमन के गृहयुद्ध में क्षतिग्रस्त तेल पाइपलाइनों से हुए गंदे तेल के रिसाव ने लाल सागर के तटीय जलमार्गों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे मछलियाँ, प्रवाल भित्तियाँ और अन्य समुद्री जीवों में कुपोषण और जनसंख्या में गिरावट आई है। चार साल से अधिक समय से जारी संघर्ष के बीच, आसपास के गाँवों के मछुआरों ने लगभग 60% कम उपज दर्ज की है, जिससे उनकी आजीविका भी दाव पर है। सूदान में खार्तूम में जल आपूर्ति प्रणालियों का विनाश स्थानीय निवासियों को पीने के पानी के अभाव में तड़पने को मजबूर कर देता है, और इतना ही नहीं, टैंकों की भारी आवाजाही और बमबारी ने भूजल स्रोतों में विभिन्न भारी धातुओं और रसायनों का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा दिया है।

भूमि का दुष्प्रभाव युद्ध का एक और भयावह आयाम है। इथियोपिया के तिगरे क्षेत्र में बिखरे विस्फोटक अवशेष और जंग लगे कम से कम 1.5 करोड़ से अधिक अनएक्सप्लोडेड बम-खांचा खेतों में दबे हुए हैं। ऐसे ज़हरीले अवशेष जमीन की उर्वरता को बर्बाद कर देते हैं और किसानों के लिए अपने खेतों में बीज बोने को जोखिमभरा बना देते हैं। अफ़ग़ानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में तो एक अनुमान के मुताबिक 10% कृषि योग्य जमीन आज भी माइन ब्लास्ट का खतरा लिए बैठे हैं, जिससे वर्षों पहले हुई लड़ाइयों का प्रभाव आज भी किसानों की पीठ पर बोझ बनकर टिका है। वन-क्षेत्र और जैव विविधता भी युद्ध में हुए जानलेवा हमलों से नहीं बच पाते। म्यांमार में चले गृहयुद्ध ने हजारों हेक्टेयर वर्षावनों को राख में तब्दील कर दिया था।। इन जंगलों में पनपने वाले दुर्लभ प्राणी जैसे इंडोचाइनीज टाइगर, एशियाई हाथी और पक्षियों की कई प्रजातियाँ आश्रय और भोजन के स्रोत खो बैठी हैं। फ़िलिपींस के दक्षिणी हिस्सों में विद्रोहियों और सेना के बीच जंगल कटाई ने केवल पेड़ों को नहीं काटा, बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जीवन-शैली और सांस्कृतिक विरासत को भी तार-तार कर दिया। युद्धों का गहरा असर जलवायु परिवर्तन पर भी दिखता है। भारी हथियारों की आवाजाही, टैंक और युद्धक वाहनों का लगातार परिचालन, विस्फोटक खाद्य-कऑम्बस्टन के उच्च उत्सर्जन- ये सब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का भारी भार वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस तथ्य को और गंभीर बनाता है कि अगर वर्तमान वैश्विक सैन्य गतिविधियों को एक राष्ट्र के शीतलन में रखा जाए, तो वह कार्बन उत्सर्जन के मामले में दुनिया के शीर्ष दस देशों में शुमार हो जाएगा। परमाणु अस्त्रों के संग्रह और तैनाती से उत्पन्न रेडिएशन रिसाव का खतरा तो और भी भयावह है: किसी एक बड़े परमाणु हमले के बाद 'न्यूक्लियर विंटर' जैसी स्थिति से विश्व का तापमान 5–10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे विश्वव्यापी कृषि अव्यवस्था और अभूतपूर्व भूखमरी की स्थिति बन सकती है।

युद्ध ने लोगों को उनके घरों से बेघर भी किया है, और इन विस्थापितों का दबाव नए रहने के स्थानों पर पर्यावरणीय संकट को और गहरा कर देता है। इतिहास गवाह है कि पहले विश्वयुद्ध और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भी लाखों एकड़ वन-क्षेत्र, नदी-तट और जमीन की सतह अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई थी। समय है आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि ठहर कर सोचने एवं ठोस कदम उठाने का है। युद्ध के पर्यावरणीय प्रभावों को रोकने के लिए एक वैश्विक संधि आवश्यक है, जिसमें 'पर्यावरणीय युद्ध अपराध' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में युद्ध की समाप्ति के बाद प्रभावी पुनर्वनीकरण (रीफ़ॉरेस्टेशन) और भूमि पुनर्स्थापन अभियानों को अनिवार्य करना चाहिए। सैन्य उपकरणों में ग्रीन टेक्नोलॉजी का समावेश—जैसे इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन-चालित वाहनों का प्रयोग—कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। शांति समझौतों में वातावरणीय मुआवजा निधि की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि युद्धविराम के बाद नागरिक और प्रकृति दोनों को समान न्याय मिले। इस लेख का उद्देश्य केवल संबोधन करना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार न सिर्फ़ इंसान, अपितु हमारी मातृभूमि और प्राकृतिक दुनिया भी है। अगर हमने आज नहीं सोचा, नहीं संवैधानिक स्तर पर विचार-विनिमय किया और नीतिगत सुधार नहीं किए, तो कल हमारे बच्चे और विश्व के सभी देशों के लोग भी इस विनाश के खंडहरों के बीच शांति की आस निहारते रह जाएंगे। समय है संभलने का, क्योंकि पृथ्वी को और इंसान को अब और प्रतीक्षा का अधिकार नहीं रहा।

प्राकृतिक चिकित्सा: शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर अपने शरीर की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव, थकान, पाचन संबंधी समस्याएं और अनिद्रा जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। ऐसे में, प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) एक वरदान साबित होती है। यह कोई शौक या विलासिता नहीं, बल्कि "अंतर्मुखी जागरूकता की अनिवार्यता" है। यह पद्धति प्रकृति के पाँच तत्वों – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश – का उपयोग करके शरीर की स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता को जगाती है।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

मेरे अनुभव में, प्राकृतिक चिकित्सा ने मुझे सिखाया

हाइड्रोथेरेपी (जल चिकित्सा): शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर ऊर्जा और ताजगी प्रदान करती है।

मिट्टी चिकित्सा: त्वचा और पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करती है, शरीर को ठंडक पहुंचाती है।

सूर्य स्नान: प्राकृतिक रूप से विटामिन डी के स्तर को संतुलित करता है और मन को शांत करता है।

प्राणायाम और ध्यान: मानसिक स्पष्टता लाते हैं, तनाव कम करते हैं और श्वसन क्षमता में सुधार करते हैं।

आयुर्वेद और योग: प्राचीन ज्ञान का आधुनिक उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, आयुर्वेद और योग ने मेरे अनुभव को और भी समृद्ध बनाया। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों साल पहले था।

आयुर्वेद: जीवन का विज्ञान

आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। इसने मुझे अपनी व्यक्तिगत प्रकृति (दोष- वात, पित्त, कफ) को समझने में मदद की। मुझे पता चला कि मेरी प्रकृति के अनुसार कौन-सा आहार और जीवनशैली मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। यह ज्ञान शरीर की जरूरतों को समझने और उसके अनुसार सही चुनाव करने में सहायक है।

योग: शारीरिक और मानसिक संतुलन का आधार

योग ने मेरे शरीर में अद्भुत लचीलापन और मानसिक एकाग्रता बढ़ाई। विभिन्न आसनों जैसे सूर्य नमस्कार ने पूरे शरीर को सक्रिय किया, जबकि शवासन ने गहन विश्राम प्रदान किया। प्राणायाम (श्वास-नियंत्रण) ने मेरे फेफड़ों को मजबूत किया और मन को शांत किया, जिससे विचारों में स्पष्टता आई। प्रकृति के हरे-भरे वातावरण में योग का अभ्यास करना किसी ध्यान से कम नहीं था, जिसने मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया।

स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति: घर पर करें शुरुआत, केंद्र पर करें विस्तार

मेरा यह अनुभव एक स्पष्ट संदेश देता है: स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, और यह कोई शौक नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं, जीवन की कोई भी उपलब्धि हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के सभी उपाय दिए हैं– हमें बस उन्हें अपनाने की आवश्यकता है।

आपके लिए एक्शन प्लान: घर पर कैसे करें शुरुआत?

सुबह की दिनचर्या में बदलाव

जल्दी उठें: प्रतिदिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें।

गुनगुना पानी: सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, यह शरीर की सफाई में मदद करता है।

हल्का व्यायाम: रोजाना 15-30 मिनट योग, प्राणायाम या तेज सैर करें।

धूप स्नान: रोजाना 10-15 मिनट सुबह की हल्की धूप लें, यह विटामिन डी के लिए आवश्यक है।

चबा-चबा कर खाएं: भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले या सोने से 2-3 घंटे पहले करें।

प्राकृतिक भोजन: बाजार के खाद्य पदार्थों, अतिरिक्त चीनी और जंक फूड से बचें। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज को प्राथमिकता दें।

ध्यान/प्राणायाम: रोजाना 10-15 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें।

प्रकृति से जुड़ें: आस-पास के पार्कों या हरियाली वाली जगह पर समय बिताएं।

यदि संभव हो, तो साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए गहन आयुर्वेदिक पंचकर्म या नेचुरोपैथी कार्यक्रम में भाग लें। यह शरीर की गहरी सफाई और पुनर्वास के लिए अत्यंत प्रभावी होता है।

स्वयं से जुड़िए, स्वस्थ रहिए

यह अनुभव मेरी तरफ से एक हार्दिक और अनुभव-सिद्ध सलाह है। हम अक्सर धन, पद और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे तो ये सब व्यर्थ हैं। मेरा मानना है कि "प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना ही सच्ची स्वस्थ जीवनशैली है।" आज ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का निर्णय लें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन निरंतर बने रहें। प्रकृति आपको अवश्य पुरस्कृत करेगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अपने शरीर से संवाद कीजिए, उसकी भाषा को समझिए, और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए।

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं **त्वरित, पारदर्शी और आसान**

520
शासकीय सेवाएं
घर बैठे, एक क्लिक में

नागरिकों के लिए सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं

R.O. No. : 13930/ 2

95.9%
आवेदनों का निराकरण

- **38 लाख+** आवेदन
- **16,700+** सेवा केंद्र
- **36 विभाग** एक मंच पर

प्रमुख सेवाएं
- ✓ **जाति प्रमाण** पत्र
- ✓ **आय प्रमाण** पत्र
- ✓ **निवास प्रमाण** पत्र
- ✓ **विवाह प्रमाण** पत्र
- ✓ **राशन कार्ड** सेवाएं
- ✓ **पेंशन** योजनाएं
- ✓ नाम **परिवर्तन सेवा**
- ✓ व्यापार **लाइसेंस**

अधिक जानकारी हेतु **स्कैन करें**

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार
sewasetu.cgstate.gov.in
92034 06400

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)